भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)

11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह का चेन्नई में 7 फरवरी 2013 को दिया गया वक्तवय

यूपीए की कूटनीति पूरी तरह अस्तव्यस्त

कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर यूपीए सरकार की रणनीति न केवल अस्तव्यस्त है बल्कि बेमेल और असंगत भी है। इच्छा शक्ति और अमल की भावना के अभाव के कारण ***पिछले आठ वर्षो या उसके बाद भी यूपीए सरकार के अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध खराब हुए हैं।***

एक तरफ पाकिस्तान भारत विरोधी नीतियों को जारी रखे हुए है और दूसरी तरफ चीन चारों तरफ से भारत को घेरने में लगा है। ***भारत के सामरिक हितों के खिलाफ पाकिस्तान चीन के साथ एक के पीछे एक काम कर रहा है। हाल में उसने ग्वादर बंदरगाह का प्रबंध नियंत्रण चीन के हाथ में देकर उसे अरब सागर के नजदीक एक मजबूत पकड़ दे दी। यहां तक कि भारत के परम्परागत पड़ोसी श्रीलंका ने भी हम्बनतोता बंदरगाह तक चीन को पहुंच देकर उसके साथ सामरिक भागीदारी की तैयारी कर ली है।***

श्रीलंका का भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों का दिलचस्प इतिहास रहा है। यूपीए सरकार ने जातीय तमिल मुद्दे पर अनेक समझौते किये हैं और उसके कथित युद्ध अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव को रोकने में मदद की है। श्रीलंका ने कथित उत्पीड़नों की जांच और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एलएलआरसी (सीखे हुए सबक और मेलमिलाप आयोग) नाम का एक विशेषज्ञ समूह गठित किया। एलएलआरसी करीब दो वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट दे चुका है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

श्रीलंका सरकार ने अपने संविधान में 13वें संशोाध्न के साथ तमिल प्रांतों को अधिकार हस्तांतरित करने का वादा किया था। ***यूपीए सरकार की उम्मीदें 13वें संशाधेान के भरोसे थी जिसमें सम्मिलित राजनीति और पुनर्वास प्रयासों को बढ़ाने का वादा किया गया था। अब श्रीलंका सरकार इस तरह के किसी वादे से इंकार कर रही है। यूपीए सरकार की यह एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है। भाजपा प्रधानमंत्री से मांग करती है कि कूटनीतिक चैनलों के जरिये श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के राहत, पुनर्वास और अधिकार सम्पन्न बनाने का मुद्दा उठाया जाए।***

यूपीए सरकार को तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाना चाहिए, जो पाल्क जलडमरूमध्य में मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। इन मछुआरों को बार-बार परेशान किया जाता है और पिछले कई वर्षो में श्रीलंका की नौसेना के हाथों मारे गए हैं। यूपीए सरकार को अपने मछुआरों की सलामती और सुरक्षा के लिए श्रीलंका सरकार से बात करनी चाहिए।

कावेरी जल विवाद मुद्दा

उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय को अधिसूचित करने के लिए 20 फरवरी की अंतिम समय सीमा तय की है। ***देश में पानी एक संवेदनशील और राजनैतिक मुद्दा है। यूपीए सरकार को इस मुद्दे को सावधानी से निपटाना चाहिए क्योंकि फैसले का अंतर-राज्य संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अंतिम निर्णय अधिसूचित होने से पहले प्रधानमंत्री को तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित कर उन्हें साथ बैठाकर बात करनी चाहिए और आम सहमति बनानी चाहिए।***

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का आदेश 5 फरवरी 2007 को पारित होने के बाद 6 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। केन्द्र में सत्ता में मौजूद सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत में बढ़ती 'सांस्कृतिक असहिष्णुता'

कुछ सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर हाल में उठे विवादों को लेकर भाजपा चिंतित है। विविध और नये विचारों को जगह नहीं देकर हम भारत को एक असहिष्णु समाज में बदलने का खतरा पैदा कर रहे हैं।

चूंकि फिल्में, संगीत, पुस्तकें और जन संदेश के सृजनात्मक मॉडल वैकल्पिक विचारों को बढ़ावा देने के वाहक के रुप में काम करते हैं, उन्हें आगे पनपने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। जो लोग इन विचारों के विरोधी हैं उन्हें असहमति में अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है लेकिन गुंडागर्दी, ब्लैकमेल और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।

संविधान में प्रतिष्ठापित अभिव्यक्ति की आजादी मुकम्मल नहीं है क्योंकि यह जिम्मेदारी की भावना से निकली है। सामुदायिक पहचान महत्वपूर्ण है और उसकी संवेदनशीलता को जान-बूझकर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इनके बहाने अपनी बात थोपकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और देश में कला और संस्कृति पर किसी प्रकार की स्वस्थ बहस का गला घोंट रहे हैं।

सांस्कृतिक मुद्दों पर बढ़ती असहिष्णुता पर जानकारी से परिपूर्ण सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। भारत कला, संस्कृति और संगीत के मामले में सदियों से एक सहिष्णु समाज है। समय आ गया है जब इस प्रगतिशील और परम्परागत विचार की फिर से पुष्टि करनी चाहिए।

(ओ.पी. कोहली)
मुख्यालय प्रभारी